

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—सण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं○ 143]

नई विरुली, शनिवार, प्रप्रैल 30, 1977/वैशाख 10, 1899

No. 143]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 30, 1977/VAISAKHA 10, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सर्व ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April 1977

G.S.R. 209(E).—The following Proclamation by the President is published for general information

Whereas, I, Basappa Danappa Jath, Vice-President acting as President of India, am satisfied that a situation has arisen in which the Government of Punjab cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution"),

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

(a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;

- (b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament, and
- (c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely—
 - (i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State,
 - (ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely
 - so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;
 - so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the report submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;

articles 163 and 164;

- so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State; article 167 and so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State;
- clause (1) and sub-clause (a) of clause (2) of article 174, articles 175 to 178 (both inclusive), clauses (b) and (c) of article 179 and the first proviso to that article and articles 180 and 181,
- so much of article 186 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly, articles 188, 189, 193, 194, 195 and 196, article 198, clauses (3) and (4) of article 199, articles 200 and 201;
- so much of clause (3) of article 202 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly, articles 208 to 211 (both inclusive), the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213, and
- so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;
- (iii) the Legislative Assembly of the said State is hereby dissolved,
- (iv) any reference in the Constitution to the Governor shall in relation to the said State be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the House

thereof shall be construed as references to the President and to Parliament or the Houses thereof respectively:

- Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;
- (v) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution, and the Punjab General Clauses Act, 1898 (Punjab Act 1 of 1898), as in force in the State of Punjab, and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State.

New Delhi.

B D JATTI.

The 30th April, 1977

Vice-President acting as President.

[No. V/11013/3/77-S&P(DV)]

New Delhi; The 30th April, 1977 T. C. A SRINIVASAVARADAN, Secy.

ORDER

New Delhi, the 30th April 1977

G.S.R. 210(E).—The following Order by the President is published for general information:

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 30th day of April, 1977, by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Punjab and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State

New Delhi:

B. D. JATTI.

The 30th April, 1977.

Vice-President acting as President.

[No. V/11013/3/77-S&P(DV)]

T. C A. SRINIVASAVARADAN, Secy.

New Delhi;

The 30th April, 1977.

गृह मंत्रालय

ग्रधिसूचना

नई दिल्ली, 30 धप्रैल, 1977

सा॰का॰िन॰ 209 (प्र).—राष्ट्रपति बारा जारी की गई निम्नलिखित उद्घोषणा सर्व-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है:

यतः मेरा, भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य्यकरते हुए उपराष्ट्रपति, बसप्पा दानप्पा जत्ती का समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें कि पजाब राज्य का शासन भारत के सविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'संविधान' कहा गया है) के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है;

भ्रतः श्रव मैं, सिवधान के भ्रनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली भ्रन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उद्घोषणा करता हू कि मैं:---

- (क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य श्रीर उस राज्य के राज्यपाल में निहित या एतद्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में ग्रंपने हाथ में लेता हूं;
- (ख) घोषित करता हूं कि उक्त राज्य के विधान मंडल की शक्तिया ससद के प्राधिकार द्वारा या ग्रधीन प्रयोक्तव्य होंगी; ग्रीर
- (ग) निम्नलिखित ग्रानुषिगक भ्रौर परिणामिक उपबन्ध करता हू जो इस उद्धोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए मुझे ग्रावश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैं, भ्रयात् :--
 - (i) इस उद्योषणा के उपर्युक्त खड (क) के भ्राधार पर अपने हाथ में लिए गए कृत्यों भ्रौर शक्तियों का प्रयोग करने में, मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस सीमा तक जिस तक मैं ठीक समझूं उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा ;
 - (ii) उस राज्य के सबध में संविधान के निम्नलिखित उपबन्धों के प्रवर्त्तन को एतद्-बारा निलम्बित किया जाता है, प्रथीत् :-
 - श्चनुच्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने का संबध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मडल को निदेश करने से हैं ;
 - श्चनुच्छेद 151 के खड़ (2) का उतना भाग जितने का संबंध भारत के नियत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के राज्य विधान मड़ल के समक्ष रखे जाने से है;

धनुष्ठेव 163 भीर 164;

- अनुच्छेद 166 के खड़ (3) का उतना भाग जितने का सबध राज्य सरकार के कार्यों का मित्रियों के बीच आवटन से हैं; अनुच्छेद 167 और अनुच्छेद 169 के खड़ (1) का उतना भाग जितने का सबध राज्य की विधान समा द्वारा संकल्प के पारित किए जाने से हैं;
- श्रनुच्छेद 174 का खंड (1) श्रीर खंड (2) का उनखंड (क); श्रनुच्छेद 175 से 178 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलिन हैं); श्रनुच्छेद 179 का खेड (ख) श्रीर (ग) श्रीर उस श्रनुच्छेद का प्रयम परन्तुक श्रीर श्रनुच्छेद 180 श्रीर 181;
- अनुच्छेद 186 का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के उराध्यक्ष के सबनमों भीर भलों से हैं; अनुच्छेद 188, 189, 193, 194, 195 तथा 196; अनुच्छेद 198, अनुच्छेद 199 का खड़ (3) और खंड (4); अनुच्छेद 200 भीर 201;
 - अनुच्छेद 202 के खड़ (3) का उतना भाग जिनने का सबंब विज्ञान सना के उपाध्यक्ष के सबन ों और भतों से हैं; अनुच्छेर 203 से 211 तक (जिननें यह दोनों सम्मिलित हैं), अनुच्छेर 213 के खंड (1) का परन्तुक और खंड (3) का परन्तुक, और
- ध्यनुच्छेद 323 के खड़ (2) का उतना भाग जिनने का सबध ज्ञारन सिहन रिसोई को राज्य के विधान मंडल के सनक्ष रखें जाने से हैं;
- (iii) उक्त राज्य की विधान सभा एतद्वारा विवटित की जाती है;
- (:V) सिवधान में राज्य राल के प्रति किसी निरेश का स्वर्थ उस राज्य के सब्ब में राष्ट्र रिन के प्रति निरेश लगाया जाएगा और उसमें राज्य के विभाग महत्त या विभाग सभा के प्रति किसी निरेश का, जहां तक उसका संबंध उसके कृत्यों और उसकी शक्तियों से हैं, अर्थ जब तक कि सन्दर्भ में अन्यया स्रोकित न हो, समद के प्रति निरेश लगाया जाएगा, और विशिष्टनया अनुष्ठेद 213 में राज्य राल और राज्य विधान महल या विधान सभा के प्रति निरेश का सर्थ क्रयग राष्ट्र पति और संसद या उसके सद नो के प्रति निरेश लगाया जाएगा।
- परन्तु इसमें की कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से लेकर अनुच्छेद 159 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलन हैं) अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा

द्वितीय मनुसूची के पैरा 1 से लेकर पैरा 4 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेंगे और न राष्ट्रपति को इस खण्ड के उपख्या (1) के प्रधीन उस सीमा तक जहां तक यह ठीक समझे, उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेगी;

(V) संविधान में राज्य के विधान मंडल के या एतद्वारा बनाए गए श्रिधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निर्वेश का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानों उसके अन्तर्गत इस उद्धोषणा के आधार पर संसद् द्वारा या राष्ट्रपति या संविधान के अनुक्छेद 357 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) में निर्विष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति निदेश हैं, और पंजाब साधारण खण्ड अधिनियम, 1898 (पंजाब 1898 का अधिनियम 1), जिस रूप में पंजाब राज्य में लागू हैं और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 के 10वें) का उतना भाग जितना राज्य विधियों पर लागू है, ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में ऐसे प्रभावी होगा मानो यह उस राज्य के विधान मंडल का अधिनियम हो।

नई **दि**ल्ली, 30 <mark>प्रप्रैल, 1</mark>977 बसप्पा दानप्पा जली, राष्ट्रपति के रूप में कार्यं करते हुए उप-राष्ट्रपति ।

[सं॰ 11013/3/77-एस॰ एड पी॰ (डी॰-V)]

टी० सी० ए० श्रीनिवासवरदन, सर्विव ।

। नई दिल्ली, 30 भ्रप्रैल, 1977

भ्रादेश

नई दिल्ली, 30 भ्राजैल, 1977

सा॰का॰ित 210 (ग्न).--राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित ग्रादेश सर्व-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज 1977 को अप्रैल के तीसवें दिन जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) का अनुसरण करते हुए में एतद्वारा निदेश देता हूं कि पंजाब राज्य सरकार के सभी कृत्य और सविधान के अधीन या उस राज्य में

प्रवृत्त किसी विधि के भ्रधीन उस राज्य के राज्यपाल में निष्ठित या प्रयोक्तब्य सभी शक्तिया, जिनको राष्ट्रपति उक्त उद्घोषणा के खण्ड (क) के भ्राधार पर भ्रपने हाथ में ले लिया है, राष्ट्रपति के भ्रधीक्षण, निदेशन भ्रौर नियन्नण के श्रध्याधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी।

नई दिल्ली; .30 धप्रैल, 1977 बसप्पा दानप्पा जत्ती, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति ।

[स॰ V/11013'3'77-एस॰ एड पी॰ (डी॰-V)]

नई दिल्ली, 30 श्रप्रैल, 1977 टी सी प्रशीनिवासवरदन, सचिव।